Drishti IAS

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

अक्तूबर 2023 (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ 3
- मुख्यमंत्री ने 'स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना' का किया शुभारंभ 6
- मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों के हित में बड़ा फैसला 9
- 'एसडीजी बेसलाईन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़' का विमोचन 9
- बस्तर की देवगुड़ियाँ और मातागुड़ियाँ हुई लिपिबद्ध 11
- परिवहन मंत्री ने राज्य का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का किया शुभारंभ 13
- मधुमक्खी और रेशम कीट पालकों को मिलेगा बिना ब्याज का ऋण 14
- मुख्यमंत्री ने 'छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना' का किया शुभारंभ 15
- राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 9 नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ 16
- चौथी छत्तीसगढ़ राज्य महिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप 8 अक्तूबर से 30 नवंबर तक 18
- 'छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना' शुरू 19
- 'छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना' शुरू 19
- बिलासपुर से नई दिल्ली के लिये सीधी विमान सेवा की सुविधा जल्द होगी शुरू 20
- हिमांगी हालदार को मिला इनोवेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार 21
- प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिये अधिसूचना जारी 22
- मतदाता जागरूकता के लिये मीडिया संस्थान होंगे 'राष्ट्रीय मीडिया सम्मान-2023' से सम्मानित 22
- राजभवन में आयोजित होगा 'मेरी माटी मेरा देश-अमृत कलश यात्रा' 23
- राज्य में हरित पटाखों का ही होगा विक्रय एवं उपयोग, दीवाली में 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे 24

नोट :

छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

2 अक्तूबर, 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग ज़िले के नगर पालिका अमलेश्वरडीह में राज्य स्तरीय एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि शिव शक्ति क्रीडा मंडल और नगर पालिका अमलेश्वरडीह छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्त्वावधान में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है।
- राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में लगभग 64 टीम भाग ले रही हैं। जिसमें से पुरुष वर्ग की 40 और महिला वर्ग की 24 टीम शामिल हैं। प्रतियोगिता में शामिल टीमों के लिये आकर्षक पुरस्कार भी दिया जाएगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टेनिस, तीरंदाजी, हॉकी सहित विभिन्न खेल अकादमियों की शुरुआत की गई है, जिससे छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिल रहा है। प्रदेश के खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिये हो रहा है।
- उन्होंने कहा कि परंपराओं को सहेजने के क्रम में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई है और भौंरा, बाटी, पिट्ठूल, कबड्डी, खो-खो, फुगड़ी जैसे परंपरागत खेलों को इसमें शामिल किया है।

मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया वूमेन हॉकी टूर्नामेंट में राज्य खेल अकादमी बहतरई बिलासपुर की टीम ने जीता फाइनल

चर्चा में क्यों ?

2 अक्तूबर, 2023 को मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया वूमेन हॉकी टूर्नामेंट 2023 में छत्तीसगढ़ की टीम स्वर्गीय बी.आर. यादव राज्य खेल अकादमी छत्तीसगढ़ (आवासीय एक्सीलेंस सेंटर) बहतरई बिलासपुर ने एक रोमांचक मुकाबले में साईं मुंबई को 4 के मुकाबले 5 गोल से पराजित कर फाइनल मुकाबला जीत लिया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- अमरावती महाराष्ट्र में आयोजित इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीम शुरुआत से ही बेहतर प्रदर्शन कर फाइनल में पहुँची थी। फाइनल मैच में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए गीता यादव, रुक्मणी, अनीता, संपदा और ममता सभी ने 1-1 गोल दागे।
- इससे पहले हुए मुकाबले में स्वर्गीय बी.आर. यादव राज्य खेल अकादमी छत्तीसगढ़ (आवासीय एक्सीलेंस सेंटर) बहतरई बिलासपुर की टीम ने पटना को 4-0 से, कोलकाता को 2-0 से पराजित किया और स्टील प्लांट दिल्ली से 1-1 गोल की बराबरी कर फाइनल में प्रवेश किया।
- पहले मैच में गीता यादव ने 2 गोल, दूसरे मैच में जाह्नवी ने 01 गोल और सेमीफाइनल में मधु सीडर ने 01 गोल दागे थे। इसके अलावा टीम के अन्य सदस्य संप्रदाय निर्मलकर, ममतेश्वरी लहरे, रुक्मणी खुसरो, अनीता खुसरो, यशोदा, मीनाक्षी उमरी, भूमिका धनकर, दामिनी खुसरो, करुणा साहू, अक्षिता आहूजा, अंजलि बंजारे, ट्विंकल, डोली, स्मिता ने भी पूरे टूर्नामेंट में बेहतर खेल का प्रदर्शन किया।

प्रधानमंत्री ने जगदलपुर में लगभग 27,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित कीं

चर्चा में क्यों ?

- 3 अक्तूबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले के जगदलपुर में लगभग 27,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और राष्ट्र को समर्पित किया।

प्रमुख बिंदु

- इन परियोजनाओं में रेलवे और सड़क क्षेत्र की कई परियोजनाओं के साथ-साथ बस्तर ज़िले के नगरनार में 23,800 करोड़ रुपए से अधिक के एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के स्टील प्लांट का लोकार्पण शामिल है।
- 23,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित स्टील प्लांट एक ग्रीनफील्ड परियोजना है, जो उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का उत्पादन करेगी।

नोट :

- नगरनार में एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का स्टील प्लांट प्लांट के साथ-साथ सहायक और डाउनस्ट्रीम उद्योगों में हज़ारों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
- यह बस्तर को दुनिया के इस्पात मानचित्र पर स्थापित करेगा और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
- पूरे देश में रेल बुनियादी ढाँचे में सुधार के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, कार्यक्रम के दौरान कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया और राष्ट्र को समर्पित की गईं।
- प्रधानमंत्री ने अंतागढ़ और तारोकी के बीच एक नई रेल लाइन और जगदलपुर एवं दंतेवाड़ा के बीच एक रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की।
- उन्होंने बोरीडांड-सूरजपुर रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी।
- प्रधानमंत्री ने तारोकी-रायपुर डेमू ट्रेन सेवा को भी झंडी दिखाई।
- इन रेल परियोजनाओं से राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। बेहतर रेल बुनियादी ढांचे और नई ट्रेन सेवा से स्थानीय लोगों को लाभ होगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।
- प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग-43 के 'कुनकुरी से छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा खंड'तक एक सड़क उन्नयन परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। नई सड़क से सड़क कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा।

नोट :

मुख्यमंत्री ने 'स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना' का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 3 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये स्कूल शिक्षा विभाग की नवाचारी 'स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना' का अपने निवास कार्यालय से ऑनलाइन शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत प्रदेश के 146 विकासखंड मुख्यालयों और चार शहरों- रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा सहित 150 कोचिंग सेंटर के माध्यम से शासकीय स्कूलों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग दी जाएगी।

नोट :

- मुख्यमंत्री बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे के समक्ष स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना संचालन के लिये स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम एवं ऐलन करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार ब्रॉशर का विमोचन किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण सहित दूरस्थ अंचल तक बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये 753 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेज़ी एवं हिन्दी माध्यम के स्कूल संचालित हो रहे हैं। राज्य में आज शुरू की गई स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय और एक अहम कदम साबित होगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत कोचिंग के साथ-साथ शिक्षकों की समुचित व्यवस्था की गई है। एक कोचिंग सेंटर में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं गणित विषय के लिये अलग-अलग नोडल शिक्षक चिह्नांकित कर लिये गए हैं।
- कोचिंग सेंटरों में अध्यापन कार्य का नियमित अवलोकन किया जाएगा और पालकों का फीडबैक भी लिया जाएगा ऑनलाइन कक्षाओं में टू-वे संवाद रहेगा, अर्थात् विद्यार्थी विषय शिक्षकों से प्रश्न पूछ सकेंगे। इस दौरान विद्यार्थियों का लगातार आकलन किया जाएगा।
- प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला ने स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के संबंध में बताया कि प्रदेश के 146 विकासखंड और चार शहरों- रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा सहित 150 कोचिंग सेंटर को इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर से जोड़ दिया गया है।
- यहाँ कक्षा 12वीं में गणित एवं जीव विज्ञान संकाय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी। यह नि:शुल्क कोचिंग हिन्दी और अंग्रेज़ी माध्यम के छात्रों के लिये दी जाएगी।
- इस योजना के तहत अब तक 9 हज़ार 13 बच्चों का पंजीयन हो चुका है। इनमें नीट के लिये 6 हज़ार 553 और जेईई की कोचिंग के लिये 2 हज़ार 460 ने पंजीयन कराया है।

नोट :

श्री रविन्द्र चौबे जी
चिंग योजना
. लि. का

गढ़ शासन एवं
इंस्टीटयूट प्रा. लि. का
न्वित प्रयास
ANI

स्वामी आत्मानंद

नोट :

मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों के हित में बड़ा फैसला

चर्चा में क्यों ?

- 3 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए आयोग की परीक्षाओं के दस्तावेज़ के विनष्टीकरण की व्यवस्था में बदलाव लाने के निर्देश दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में राज्य शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को आयोग की परीक्षाओं की आंसर सीट एवं दस्तावेज़ों के विनष्टीकरण की अवधि को दो साल किये जाने का प्रस्ताव भेजा गया है।
- गौरतलब है कि पीएससी परीक्षाओं की आंसर सीट एवं दस्तावेज़ के विनष्ट किये जाने के कायदे-कानून छत्तीसगढ़ राज्य में लंबे समय से चले आ रहे हैं। इसमें बदलाव लाने के लिये मुख्यमंत्री ने आवश्यक निर्देश दिये हैं।

'एसडीजी बेसलाईन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़' का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

4 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के संबंधित राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई 'एसडीजी बेसलाईन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़'का विमोचन योजना भवन, नवा रायपुर में किया।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी के विभिन्न लक्ष्यों में राज्य द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क में शामिल 40 इंडिकेटर्स के अंतर्गत 2030 का लक्ष्य 2022 में ही हासिल कर लिया गया है। 84 इंडिकेटर्स का 2030 तक का लक्ष्य भी आगामी 2-3 वर्षों में हासिल किया जाना संभावित है।
- 'एसडीजी गोल 1 (नो पॉवर्टी)' से संबंधित इंडिकेटर के उपलब्ध हुए डाटा के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि इस गोल को आकलित करने वाले संकेतक 'मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी स्कोर'(एमपीआई स्कोर) के अनुसार राज्य में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर हुए हैं।
  - इसमें राज्य की प्रमुख योजनाएँ- राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, मुख्यमंत्री हाट बाज़ार, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, पढ़ई तुंहर द्वार इत्यादि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
  - एमपीआई स्कोर मूलत: 12 संकेतकों का इंडेक्स है, जो पोषण, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, शिक्षा एवं वित्तीय समावेशन से संबंधित होते हैं। संकेतक 'स्वास्थ्य योजना एवं बीमा कवरेज' में भी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें राज्य की प्रमुख योजना, जैसे- खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री दवापेटी योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण एवं हृदय योजना, दाई-दीदी एवं महतारी जतन योजना का महत्त्वपूर्ण योगदान है।
- 'एसडीजी गोल 2 (ज़ीरो हंगर)' के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति करने वाले संकेतक 'खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल लाभार्थी'में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएँ- अंत्योदय योजना के अंतर्गत 1 रुपए में अनाज वितरण, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, आयोडाईज्ड अमृत नमक, चना एवं शक्कर प्रदाय योजना इत्यादि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
- संकेतक 'कृषि में सकल मूल्यवर्धन'में भी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें राज्य की प्रमुख योजना, जैसे- राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कृषि बजट में उत्तरोत्तर वृद्धि, अधिकतम फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाना का मुख्य योगदान है।
- 'एसडीजी गोल 4 (क्वालिटी एजुकेशन)' के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति करने वाले संकेतक 'माध्यमिक शिक्षा में ड्रापआउट दर एवं लैंगिक समानता सूचकांक', 'प्रारंभिक शिक्षा सकल नामांकन', 'प्रशिक्षित शिक्षको का अनुपात' में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएँ- पढई तुंहर द्वार, स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल, गणवेश प्रदाय योजना, मध्याह्न भोजन प्रदाय योजना का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।

नोट :

- 'एसडीजी गोल 5 (लैंगिक समानता)' के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रदर्शन कर पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक 'स्थानीय स्व-शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व', 'महिलाओं के विरुद्ध अपराध'में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएँ- सबला योजना, पौनी पसारी योजना, महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सखी वन स्टाफ योजना, महिला कोष योजना इत्यादि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
- 'एसडीजी गोल 6 (क्लीन वाटर एंड सेनिटेशन)' के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक 'ओडीएफ लक्ष्य प्राप्ति', 'सीवेज उपचार', 'पाईप लाईन जलप्रदाय', 'उन्नत पेयजल स्रोत उपयोगकर्ता', 'शहरी एवं ग्रामीण आबादी को शौचालय सुविधा' में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएँ- ग्रामीण जल प्रदाय योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
- 'एसडीजी गोल 8 (डिसेंट वर्क एंड इकॉनमी ग्रोथ)' के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक 'ईज ऑफ डुइंग बिज़नेस स्कोर', 'बैंक खाता धारक परिवार' में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएँ- रीपा योजना, मुख्यमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना इत्यादि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
- 'एसडीजी गोल 11 (सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्यूनिटी)' के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक 'अपशिष्ट संग्रहण, संधारण एवं उपचारण', 'आवास योजना के अंतर्गत पूर्ण किये गए मकान'में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएँ- मिशन क्लीन सिटी योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना इत्यादि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
- 'एसडीजी गोल 12 (रिस्पॉन्सबल, कन्जम्शन एंड प्रोडक्शन)' के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक 'कृषि क्षेत्र में रासायनिक खाद के उपयोग में कमी', 'अपशिष्ट संयंत्रों की स्थापना', 'फसल भंडार एवं वितरण हानि में कमी', 'प्रति व्यक्ति भोजन उपलब्धता' में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएँ- यूनिवर्सल पीडीएस योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, विभिन्न सिंचाई योजना, सोलर पंप वितरण योजना एवं कृषि उपकरण वितरण योजना इत्यादि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
- राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई 'एसडीजी बेसलाईन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़'निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पथ-प्रदर्शक का कार्य करेगी। यह रिपोर्ट संबंधित विभागों को अपनी स्थानीय क्रियान्वयन प्रतिबद्धता की पहचान कर अपने हितधारकों के बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगी।
- छत्तीसगढ़ यूनिसेफ प्रमुख जॉब जकारिया ने बताया कि काफी कम राज्यों द्वारा एसडीजी संबंधित फ्रेमवर्क और उन पर आधारित रिपोर्ट जारी की गई है, जिनमें से छत्तीसगढ़ की उपलब्धि विशेष है। राज्य द्वारा मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। डिस्ट्रिक्ट स्तर के एसडीजी संबंधित ऑकड़े उपलब्ध कराने वाले राज्य अल्पतम हैं।

नोट :

बस्तर की देवगुड़ियाँ और मातागुड़ियाँ हुई लिपिबद्ध

चर्चा में क्यों ?

5 अक्टूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य शासन की मंशानुरूप छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर अंचल के आदिवासियों के विरासत में आस्था का केंद्र देवगुड़ियों-मातागुड़ियों को संरक्षित एवं संवर्धित करने की दिशा में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के द्वारा इन देवगुड़ियों-मातागुड़ियों को लिपिबद्ध किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर अंचल में सदियों से अनेक जनजातीय समुदाय निवासरत हैं। इन जनजातीय समुदायों की अपनी अलग सांस्कृतिक विरासत है। आदिवासियों के विरासत में आस्था का केंद्र देवगुड़ी-मातागुड़ी है, जिसकी जनजातीय समुदायों में अपनी महत्ता है।
- बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न मदों के अभिसरण से इन देवगुड़ियों-मातागुड़ियों का जीर्णोद्धार करने सहित उन्हें सँवारने के लिये व्यापक पहल की गई है।
- जनजातीय समुदाय के अधिकांश समूह प्रकृति पूजक हैं, वे पेड़-पौधों में अपने देवी-देवताओं का वास मानते हैं और इसी आस्था के फलस्वरूप वनों को बचाने के लिये अहम भूमिका निभा रहे हैं। यही वजह है कि इन देवस्थलों पर बहुतायत मात्रा में पेड़-पौधे पाए जाते हैं।
- इन देवस्थलों के परिसरों में वृहद स्तर पर फलदार एवं छायादार पौधरोपण किया जा रहा है। इसके साथ ही उक्त देवस्थलों का सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदान कर देवगुड़ियों एवं मातागुड़ियों सहित गोटुल एवं प्राचीन मृतक स्मारकों के भूमि को संरक्षित करने के उद्देश्य से संबंधित देवी-देवताओं के नाम से भूमि को राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है।
- वहीं इन देवगुड़ियों-मातागुड़ियों और गोटुल एवं प्राचीन मृतक स्मारकों को उनके नाम से सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र जारी किया गया है, ताकि इन सांस्कृतिक-सामाजिक धरोहरों के परिसरों को अवैध कब्जा से बचाया जा सके। साथ ही इन धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में स्थानीय जनजातीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके।
- देश में पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य एवं बस्तर संभाग देश का ऐसा संभाग है, जो आदिवासी समुदायों की आस्था एवं जीवित परंपराओं के केंद्र मातागुडी, देवगुडी, गोटूल, प्राचीन मृतक स्मारक, सेवा-अर्जी स्थल आदि के संरक्षण, संवर्धन तथा परिरक्षण के लिये प्रतिबद्ध है।
- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के तहत देवी-देवताओं के नाम से ग्राम सभा को 2453 सामुदायिक वनाधिकार पत्र प्रदान किये गए हैं। इनमें कुल 7075 मातागुडी, देवगुडी, गोटूल, प्राचीन मृतक स्मारक के लिये 2607.20 हेक्टेयर (6466 एकड़) भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि कर संरक्षित किया गया है।
- बस्तर संभाग में कुल 22884 बैगा, सिरहा, मांझी, गुनिया, गायता, पुजारी, बजनिया, अटपहरिया आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना अंतर्गत पंजीकृत करके प्रत्येक को प्रतिवर्ष 7000 रुपए प्रदान किया जा रहा है।
- बस्तर में क्षेत्रवार आदिवासी समुदायों के देवी-देवताओं की वाचिक परंपरा में प्रचलित मान्यताओं को लेखबद्ध कर उन्हें जारी किये गए सामुदायिक वन अधिकार के प्रपत्रों को संकलित कर 'पुरखती कागजात'नामक (भाग एक) पुस्तिका तैयार की गई है। 'पुरखती कागजात'(भाग-दो) में संरक्षित खसरों का संकलन है, जिसमें भुईया के माध्यम से खसरे के कैफियत कॉलम में मातागुडी, देवगुड़ी के नाम व रकबा उल्लेखित कर राजस्व अभिलेख संरक्षित किया गया है।
- बस्तर अंचल की आस्था और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में 6283 देवगुड़ी और मातागुड़ी में से 3244 का जीर्णोद्धार की स्वीकृति दी गई है और अब तक 2320 देवगुड़ी एवं मातागुड़ियों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वहीं स्वीकृत 297 गोटुल निर्माण कार्यों में से 200 कार्यों को पूर्ण किया गया है।
- बस्तर संभाग के अंतर्गत कुल 7075 देवगुड़ियों एवं मातागुड़ियों सहित गोटुल एवं प्राचीन मृतक स्मारकों में से 3619 देवगुड़ी-मातागुड़ी और गोटुल एवं मृतक स्मारक राजस्व, गैर वनभूमि, निजी भूमि तथा अन्य मदों की भूमि पर अवस्थित हैं, जिससे 898 हेक्टेयर रकबा भूमि संरक्षित है।

नोट :

- वहीं शेष सभी 3456 देवगुड़ियों-मातागुड़ियों और घोटुल एवं प्राच्य मृतक स्मारकों का सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र समुदाय को प्रदान कर करीब 1709 हेक्टेयर रकबा भूमि संरक्षित किया गया है। लगभग 6466 एकड़ राजस्व भूमि को देव-मातागुड़ी के रूप में संरक्षित किया गया है।
- बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण-
  - बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन राज्य शासन द्वारा 27 फरवरी, 2019 को किया गया था। इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सदस्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बनाया गया है।
  - प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन एवं संरक्षण करना है, इस प्राधिकरण के अंतर्गत क्षेत्र तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिये अन्य कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं।
  - प्राधिकरण अंतर्गत संभाग के बस्तर, कोंडागाँव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा ज़िले समाहित हैं।

नोट :

परिवहन मंत्री ने राज्य का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

5 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर ज़िले के अंतर्गत ग्राम धनेली में राज्य के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि शासकीय विभाग के 15 वर्ष से पुरानी सभी गाड़ियों को भी आवश्यक रूप से स्क्रैप करने का निर्णय लिया जा चुका है।
- इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को मध्य भारत के लिये वाहन स्क्रैपिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है, स्क्रैपिंग की सुविधा को बढ़ावा देने के लिये इस सेंटर को पूरी तरह डिजिटलीकृत किया गया है।
- छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत पंजीकृत व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर (आरवीएसएफ) को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की श्रेणी में रखने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। राज्य में स्थापित होने वाले आरवीएसएफ भी उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग हेतु निर्धारित छूट का लाभ ले सकते हैं।
- राज्य के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर का संचालन मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा।
- पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर से गाड़ी को स्क्रैप कराने के बाद नये गाड़ी खरीदने के लिये टैक्स में 25 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा। छूट के लिये पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर के द्वारा ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिससे सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट कहा जाएगा।
- सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जो परिवहन विभाग के वाहन सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होगा और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सभी ऑटोमोबाइल डीलरशिप में मान्य होगा।
- इसके अतिरिक्त मासिक या त्रैमासिक कर देने वाली ऐसी गाड़ियाँ जिनका टैक्स बकाया है और स्क्रैपिंग कराना चाहते हैं, उन्हें भी गाड़ी में बकाया पिछले एक साल के टैक्स, पैनल्टी और ब्याज में छूट दी जाएगी।
- स्क्रैपिंग का प्रॉसेस : जब कोई वाहन स्क्रैप सेंटर में पहुँच जाता है, तो उसे वैज्ञानिक तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। अलग-अलग चरणों की बात करें तो स्टेशन पर टायर और इंजन किट हटा दिये जाते हैं। अगले चरण में बैटरियों और फ्री-ऑन गैस किटों को नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वाहन की सीटें, स्टीयरिंग, इंजन और रेडिएटर हटा दिये जाते हैं, जिससे धातु से बना एक खोखला ढाँचा रह जाता है। धातु को ब्लॉकों में बदलने के लिये बेल प्रेस मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे बाद में विभिन्न कंपनियों को आपूर्ति की जाती है। वहीं कार के अन्य घटकों को पुनर्नवीनीकरण किया जाता है और इन्हें निजी कंपनियों को बेच दिया जाता है।

नोट :

मधुमक्खी और रेशम कीट पालकों को मिलेगा बिना ब्याज का ऋण

चर्चा में क्यों ?

5 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में राज्य में मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन को कृषि का दर्जा दिये जाने के साथ ही इसके पालकों को बिना ब्याज के ऋण सुविधा उपलब्ध कराए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- कृषि विकास एवं कृषि कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ में मधुमक्खी एवं रेशम कीट पालकों को संस्थागत अल्पकालीन एवं मध्यकालीन कृषि ऋण पर 'राज्य के कृषकों को सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021' के आधार पर प्रदान किये जाएंगे।

नोट :

- गौरतलब है कि केंद्र प्रवर्तित एकीकृत बागवानी मिशन अंतर्गत मधुमक्खी पालन की एक यूनिट की इकाई लागत 2.31 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें हितग्राहियों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
- वित्तीय वर्ष में एकीकृत बागवानी मिशन के तहत मधुमक्खी पालन के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति होने की दशा में लंबित आवेदनों को निर्धारित ऋणमान के अनुसार बैंक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जाएगा।
- मधुमक्खी पालकों को बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्राप्त ऋण पर राज्य के कृषकों को सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 के अंतर्गत सहकारिता एवं वित्त विभाग के द्वारा वहन किया जाएगा। देय ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा मुख्य योजना के समान होगी।
- इसी तरह रेशम कीट पालकों को संस्थागत मध्यकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान तथा राज्य के किसानों के समान विद्युत प्रभार में अनुदान मिलेगा।
- जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार द्वारा संचालित सिल्क समग्र-2 योजना के तहत रेशम कीट पालन करने वाले लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों को केंद्रांश और राज्यांश को मिलाकर कुल 90 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
- शहतूत पौधों पर रेशम कीट पालन हेतु प्रति एकड़ लागत 5 लाख रुपए ऋणमान के आधार पर ऋण स्वीकृति दी जाएगी।
- निर्धारित ऋणमान में सिल्क समग्र-2 में देय अनुदान के अतिरिक्त कृषक श्रेणीवार हितग्राही अंश को बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से संस्थागत ऋण कृषि फसलों की भाँति शून्य प्रतिशत ब्याज के रूप मध्यकालीन कृषि ऋण के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष में सिल्क समग्र-2 योजना के तहत प्रदेश को प्रदायित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति होने की दशा में लंबित आवेदनों को निर्धारित ऋणमान के अनुसार बैंक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा मध्यकालीन कृषि ऋण की सुविधा दी जाएगी और प्राप्त ऋण पर 03 वर्षों तक वित्त पोषण राज्य के कृषकों को सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 के अंतर्गत सहकारिता एवं वित्त विभाग के द्वारा वहन किया जाएगा।
- सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा सिल्क समग्र-2 योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नार्म्स के अनुसार कृषकों को ऋण की स्वीकृति प्रदाय की जाएगी। देय ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा मुख्य योजना के समकक्ष होगी।

मुख्यमंत्री ने 'छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना' का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

7 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 'छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना'का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को घर से कॉलेज आने-जाने के लिये नि:शुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर अमल करते हुए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना से कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस योजना के अंतर्गत शासकीय कॉलेजों और राजकीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 01 लाख से ज़्यादा नियमित विद्यार्थियों को लाभ होगा।
- इस योजना पर लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक व्ययभार आएगा, इसमें से आधा भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा एवं आधा व्यय बस संचालकों द्वारा छूट के तौर पर वहन किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिये छात्र वेबसाईट पर कॉलेज और रूट के साथ बस पास के लिये आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज लॉग इन कर सभी विवरणों की जाँच के पश्चात् आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार करेगा। स्वीकृत छात्र लॉग इन कर क्यूआर कोड युक्त अपना बस पास डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। बस कंडेक्टर द्वारा पास की जाँचकर घर से महाविद्यालय, महाविद्यालय से घर ले जाया जाएगा।
- 'छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना'के तहत छात्रों को घर से महाविद्यालय तक आने-जाने में सुविधा होगी। नि:शुल्क परिवहन से छात्रों को उच्चशिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। यह योजना छात्रों के लिये आर्थिक रूप से भी मददगार होगी। यह योजना छात्रों के समय की बचत करेगी और छात्रों के बीच सामाजिक समावेश को बढ़ावा देगी।

नोट :

राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 9 नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

7 अक्तूबर, 2023 को रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में 'राष्ट्रीय आयुष मिशन'के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नौ नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत राज्य में 'सुप्रजा आयुष मातृ एवं नवजात देखभाल', 'वयोमित्र', 'करुणा', 'आयुर्विद्या', 'एनीमिया' और 'लिम्फेटिक फाइलेरियासिस' के लिये 'रुग्णता प्रबंधन' व 'विकलांगता नियंत्रण'जैसे नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई।

नोट :

- रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में राज्य शासन के आयुष विभाग द्वारा चिकित्सकों के लिये उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।
- उन्मुखीकरण कार्यशाला के दौरान विभागीय अधिकारियों और चिकित्सकों ने स्वास्थ्य प्रणाली को और मज़बूती प्रदान करने पर विस्तृत चर्चा की। प्रारंभ हुए नए कार्यक्रमों के बारे में विभाग द्वारा जल्दी ही विस्तृत प्रशिक्षण भी आयोजित किये जाएंगे।

नोट :

चौथी छत्तीसगढ़ राज्य महिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप 8 अक्तूबर से 30 नवंबर तक

चर्चा में क्यों ?

7 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के तत्वावधान में रायपुर, भिलाई एवं दल्लीराजहरा में 8 अक्तूबर से 30 नवंबर, 2023 तक चौथी राज्य महिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इस लीग में चयनित 60 बालिका खिलाड़ियों को खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रायपुर में खेल किट वितरित किये।
- इस राज्य लीग चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने वाली टीम भारतीय महिला लीग चैंपियनशिप में भाग लेंगी।
- राज्य विमेन फुटबॉल लीग चैंपियनशिप में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के बालिका फुटबॉल अकादमी रायपुर की 50 बालिका खिलाड़ियों का भी चयन हुआ है।

नोट :

'छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना' शुरू

चर्चा में क्यों ?

7 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने हेतु 'छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना' प्रारंभ की गई है।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 15 अगस्त, 2023 को इस नवीन योजना को शुरू करने की घोषणा के परिपालन में 1 करोड़ रुपए आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दी गई है।
- योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालन शुरू करने वाले उद्यमियों को स्ववित्तीय अथवा बैंक ऋण से व्यवसायिक इकाई स्थापित पर 5 वर्ष के लिये स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- राज्य में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिये शुरू की गई इस योजना में विकसित और विकासशील विकासखंडों में कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना के लिये 25 से 40 प्रतिशत तक पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा।
- ब्रायलर, देशी कुक्कुट और रंगीन कुक्कुट इकाईयों की स्थापना के लिये 'अ'श्रेणी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
- इसी तरह 'ब'श्रेणी क्षेत्र के सामान्य हितग्राही को 35 प्रतिशत और अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
- कुक्कुट लेयर और पेरेंट कुक्कुट इकाई के लिये 'अ'श्रेणी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
- इसी तरह 'ब'श्रेणी क्षेत्र के सामान्य हितग्राही को 35 प्रतिशत और अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।

'छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना' शुरू

चर्चा में क्यों ?

7 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने हेतु 'छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना' प्रारंभ की गई है।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 15 अगस्त, 2023 को इस नवीन योजना को शुरू करने की घोषणा के परिपालन में 1 करोड़ रुपए आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दी गई है।
- योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालन शुरू करने वाले उद्यमियों को स्ववित्तीय अथवा बैंक ऋण से व्यवसायिक इकाई स्थापित पर 5 वर्ष के लिये स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- राज्य में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिये शुरू की गई इस योजना में विकसित और विकासशील विकासखंडों में कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना के लिये 25 से 40 प्रतिशत तक पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा।
- ब्रायलर, देशी कुक्कुट और रंगीन कुक्कुट इकाईयों की स्थापना के लिये 'अ'श्रेणी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
- इसी तरह 'ब'श्रेणी क्षेत्र के सामान्य हितग्राही को 35 प्रतिशत और अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
- कुक्कुट लेयर और पेरेंट कुक्कुट इकाई के लिये 'अ'श्रेणी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।

नोट :

- इसी तरह 'ब'श्रेणी क्षेत्र के सामान्य हितग्राही को 35 प्रतिशत और अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।

बिलासपुर से नई दिल्ली के लिये सीधी विमान सेवा की सुविधा जल्द होगी शुरू

चर्चा में क्यों ?

11 अक्तूबर, 2023 को केंद्र सरकार व एलायंस एयर ने विंटर शेड्यूल में सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार बिलासपुर से दिल्ली सीधी विमान सेवा चलाने की घोषणा की है। यह विमान सेवा 31 अक्तूबर से शुरू होगी।

प्रमुख बिंदु

- अब बिलासपुर से दिल्ली तक सीधी विमान सेवा सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध रहेगी। प्रयागराज के लिये भी विमान सेवा इन्हीं दिनों में उपलब्ध रहेगी, क्योंकि एक ही विमान बिलासपुर को इन दोनों शहरों से कनेक्ट करेगी।
- विमान सेवा के लिये जारी शेड्यूल के अनुसार बिलासपुर से दिल्ली जाने वाला विमान दोपहर 3 बजकर 15 मिनट पर यहाँ से उड़ान भरेगा और शाम 5 बजकर 25 मिनट पर दिल्ली में लैंड करेगा। यह विमान सुबह 9 बजे दिल्ली से उड़कर सवा 11 बजे बिलासपुर पहुँचेगा। इस तरह बिलासपुर से दिल्ली सवा दो घंटे में पहुँचा जा सकेगा।
- दिल्ली से बिलासपुर आने वाला विमान ही दोपहर करीब पौने 12 बजे प्रयागराज के लिये उड़ान भरेगा और दोपहर 1 बजे वहाँ पहुँच जाएगा। वापसी में दोपहर डेढ़ बजे प्रयागराज से उड़कर यह विमान दोपहर पौने 3 बजे बिलासपुर पहुँचेगा।
- विदित हो कि एलायंस एयर कंपनी ने 4 से 8 अक्तूबर तक बिलासपुर से दिल्ली के लिये सीधी विमान सेवा हेतु ट्रायल शुरू किया था, जो सफल रहा।
- गौरतलब है कि अंचलवासियों द्वारा बिलासपुर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे महानगरों के लिये सीधी विमान सेवा की मांग लंबे समय से की जा रही थी। वर्तमान में बिलासपुर से जबलपुर-प्रयागराज होते हुए सिर्फ एक फ्लाइट चल रही है। इसी बीच इंदौर और भोपाल के लिये विमान सेवा शुरू की गई थी। यात्रियों की कम संख्या का हवाला देते हुए इसे बंद कर दिया गया, जो अभी भी बंद है।

नोट :

हिमांगी हालदार को मिला इनोवेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

14 अक्तूबर, 2023 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय इंस्पायर मानक प्रतियोगिता में बिलासपुर के भारतमाता आंग्ल माध्यम स्कूल की छात्रा हिमांगी हालदार को राष्ट्रीय इंस्पायर पुरस्कार मिला है।

प्रमुख बिंदु

- उबालते समय दूध गिरने को रोकने के लिये हिमांगी हालदार ने एंटी मिल्ट स्पिलिंग डिवाइस तैयार की है। इसकी मदद से उबालते समय दूध नीचे नहीं गिरता। इस इनोवेशन के लिये हिमांगी को राष्ट्रीय इंस्पायर पुरस्कार मिला है।
- नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम राजघाट (विज्ञान भवन) में आयोजित सम्मान समारोह में हिमांगी को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पुरस्कार प्रदान किया।
- हिमांगी अब फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के समक्ष अपना प्रोटोटाइप प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद सकुरा प्रोग्राम के तहत जापान में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।
- इस डिवाइस की कीमत 80 रुपए तय की गई है। इसका डिज़ाइन पेटेंट हिमांगी के नाम से है।
- विदित हो कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा किये गए इनोवेशन को प्लेटफॉर्म प्रदान करना और स्कूली बच्चों में रचनात्मकता एवं नवीन सोच की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये विज्ञान और सामाजिक अनुप्रयोगों में निहित मूल विचारों/नवाचारों को बढ़ावा देना है।
- इस वर्ष ज़िला स्तर से प्राप्त सात लाख आइडिया से देशभर से 441 छात्र-छात्राओं को उनके आइडिया और प्रोटोटाइप के साथ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आमंत्रित किया गया। इसमें भारतमाता आंग्ल माध्यम स्कूल बिलासपुर की छात्रा हिमांगी हालदार के प्रोटोटाइप एंटी मिल्क स्पिलिंग डिवाइस को राष्ट्रीय स्तर पर विजेता होने का सम्मान प्राप्त हुआ।

नोट :

प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिये अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों ?

13 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम चुनाव के पहले चरण के लिये अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई।

प्रमुख बिंदु

- प्रथम चरण में बस्तर संभाग की 12 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों समेत राजनांदगाँव, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई तथा कबीरधाम ज़िलों के 08 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में दो चरणों में हो रहे निर्वाचन के पहले चरण की 20 सीटों के लिये 20 अक्तूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं।
- 21 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी तथा प्रत्याशी 23 अक्तूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।
- प्रथम चरण के लिये 07 नवंबर को मतदान होगा, जबकि दोनों ही चरणों के लिये मतगणना 03 दिसंबर को होगी।
- प्रथम चरण में कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकोट, जगदलपुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागाँव, केशकाल, कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, मोहला-मानपुर, खुज्जी, डोंगरगाँव, राजनांदगाँव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्रों के लिये मतदान होगा।

मतदाता जागरूकता के लिये मीडिया संस्थान होंगे 'राष्ट्रीय मीडिया सम्मान-2023' से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

24 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मीडिया संस्थानों को 'राष्ट्रीय मीडिया सम्मान-2023' से सम्मानित किया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि भारत निर्वाचन आयोग मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मीडिया संस्थानों का चयन कर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मीडिया सम्मान प्रदान करता है। राष्ट्रीय मीडिया सम्मान वर्ष 2023 के लिये भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया संस्थानों से 10 दिसंबर, 2023 तक आवेदन आमंत्रित किया है।
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया संस्थानों से चार श्रेणियों- प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक (टेलीविजन) मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक (रेडियो) मीडिया और ऑनलाईन (इंटरनेट)/सोशल मीडिया में पुरस्कार हेतु नामांकन आमंत्रित किया गया है।
- पुरस्कार पाने हेतु इच्छुक मीडिया संस्थान अपना आवेदन राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव (संचार), भारत निर्वाचन आयोग को उक्त समयावधि में प्रेषित कर सकते हैं। अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन तथा अनुशंसाओं को आयोग द्वारा गठित निर्णायक मंडल के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। निर्णायक मंडल द्वारा चयनित संस्थानों को 25 जनवरी, 2024 राष्ट्रीय मतदाता दिवस में सम्मानित किया जाएगा।

राजभवन में आयोजित होगा 'मेरी माटी मेरा देश-अमृत कलश यात्रा'

चर्चा में क्यों ?

25 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सी.आर.पी.एफ. एवं नेहरू युवा केंद्र के समन्वय से 'मेरी माटी मेरा देश-अमृत कलश यात्रा'का राज्यस्तरीय कार्यक्रम राजभवन में आयोजित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी ग्राम पंचायतों से भारत के शहीदों के सम्मान में घर-घर जाकर कलश में मिट्टी एकत्रित की गई है। प्रदेश के 33 जिलों के 146 विकासखंडों के अंतर्गत हर गाँव से संग्रहित मिट्टी, राजभवन लाई जाएगी।
- आज़ादी के 75वें वर्ष का जश्न मनाते हुए अमृत कलशों को राजधानी नई दिल्ली के कर्त्तव्य पथ पर पहुँचाया जाएगा। जहाँ विभिन्न राज्यों से लाई गई मिट्टी से शहीदों के सम्मान में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा।
- इस अवसर पर राजभवन में 27 अक्तूबर, 2023 को राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सी.आर.पी.एफ. के अधिकारियों ने राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से भेंट कर उन्हें कार्यक्रम हेतु आमंत्रित किया था। राज्यपाल ने भव्यतापूर्ण कार्यक्रम करने के निर्देश दिये।

नोट :

राज्य में हरित पटाखों का ही होगा विक्रय एवं उपयोग, दीवाली में 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे

चर्चा में क्यों ?

26 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में केवल हरित पटाखों का उपयोग एवं विक्रय ही हो सकेगा। साथ ही दीपावली, छठ, गुरु पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिये दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है।

प्रमुख बिंदु

- उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु ज़िला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
- दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस के मौके पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिये निर्धारित की गई है। दीपावली के लिये रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिये सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिये रात 8 बजे से रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस/नया वर्ष के लिये रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।
- शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर, 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिये गए हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गए हैं।
- साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिये बाज़ार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज़ पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है।
- पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एंटिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाइन, अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों, जैसे- फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

नोट :